तरक्की के लिए सरकार का एजेंडा

राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कुछ नये कार्यक्रम तय किए हैं। इसका मकसद एनडीए-वन के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज को और तेज करना है। अगले पांच साल के लिए यह एजेंडा तय किया गया है।

प्रशासन

■ लोक सेवा समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से जन-जन तक पहुंचे इसके लिए 'लोक सेवा गारंटी कानून' बनाया जाएगा। ■ सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनायी जाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 अंतर्गत भ्रष्ट लोकसेवकों की अवैध संपत्ति को राज्यसात करने की कार्रवाई को गति दी जाएगी। ■ राज्यकर्मियों के क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार कर कार्यान्वित किया जाएगा।